सं. मो. वि./रोहतक/2-87/3863 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० (1) परिवहन म्रायुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) जनरल मैंनेजर, हरियाणा रोडवेंज, रोहतक के श्रमिक श्रो रणबीर सिंह हैल्पर, मार्फत विजेन्द्र सिंह सिंगल विकील, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायिनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ;

इसलिए, भव, भौबोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) हारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके हारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम 78/32673, विभाक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक की विवादपस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाद तीन मास में देने हेतु निर्विष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत भवना सम्बन्धित मामला है :—

नया श्री रणबीर तिह हैल्पर, को सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का

स॰ मो॰ वि॰/कुर./15-86/3871.—चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निवेशक, हरियाणा स्टेट कोपरेटिव सप्लाई मार्कीटिंग फैडरेशन लि॰, चण्डीगढ़ के श्रीमिक श्री जय चन्द, पुत्र श्री सिम्रूटरम, गांव खेड़ी राम नगर, गांव व डा॰ पलवल, जिला कुठसेंत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक विवाद है;

भौर चूंकि इरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाधनीय समझते हैं ;

इसनिये, मन, भीदोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई कावियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिसूचना सं0 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त मिध्यूचना की धारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, प्रम्वाला, का विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा, वामिना क्यायनिर्वय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं, जो कि उनत प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है :—

क्या श्री जय चन्द्र की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत कात हकदार है ?

सं भो•वि• कुर. / 7-87 / 3877 — नूकि हरियाणा के राज्यााल को राय है कि (1) पर्विहन आ मुद्देत, हरियाणा चण्डीगढ़, (2) महा प्रवस्धक, राज्य परिवहन, कैयल के अभिक श्री कर्म चन्द्र, उराईवर, पुत्र श्री दामोदर चन्द्र, 967 / 14, छज्जूमल कालीनों, कैयल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौदागिक विवाद है;

भौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्मय हुतु निर्दिष्ट करना वाकनोय समझते हैं;

इसलिये, अब, भोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को घारा 10 को उनधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान को गई शिवतयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारों अधित्वता तं 3(44) 84-3-अन, दिनाक 18 अत्रैत, 1984 द्वारा उनत अधिसूचना की घारा 7 के अधीन गठित अमन्यायालय, अन्याला को विवादप्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाद तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अभिक के बोच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से म्युसंगढ- धयका संबंधित मामला है:—

क्या भी कर्म चन्द इराईवर की सेवामों का समापन न्यायोचित वया ठीक है ? यदि तहीं, तो वह किस राहतु का हकवार है ?

सं शो वि । रोहतक 4-81/3884 - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणी कि स्वाधित की प्राप्त के प्राप्त की स्वाधित की प्राप्त की हरियाणा रोड़वेज, रोहतक के श्रामिक श्रा सज्जन कुमार, पुत्र श्री हरियन्द, गांव वालमबा, तहसील विज्ञा रोहतक तथा उसके प्रवन्धकों के बाव इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई शौद्योगिक विवाद है;

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल दिवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अविनियम, 1947 की बार। 10 की उप-घारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई मक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641—1-अम 78/32573, दिनांक 6 नवस्वर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को बिबादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त सामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:——

क्या श्री सन्द्रत कुनार की रोजाओं का प्रनान न्यायो नित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

संग्री विग्/भिवानी/2-87/3892 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं । (1) सचिव, पी. बन्लयू. डी., पञ्सक हैल्य हिमाटंमैंट, हरियाणा, चाड़ीगढ़, (2) कार्यकारी ग्रीभागता पी. इन्लयू. डी., पञ्लिक हैल्य डिविजन नं० 2, भिवानी के श्रीमक श्री कृष्ण पुत्र श्री हरनारायण, सुभाष स्ट्रीट, भिवानी तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई भोद्योगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिवतयों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उनत प्रयन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उनत विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री कृत्य की सेताओं का समान न्यायोजित तथा ठीन है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का इकवार है ?

सं० ग्रो॰ वि॰ /सोनोरन/148-86/3910—-चूंकि हिरियाणा के राज्यताल की राय है कि मै॰ गैडोर टूल्ज इण्डिया प्रा॰ लि॰, कुंग्डनी, सोनोरत के श्रमिक श्रो सुगात चन्द्र, ई ई-2065 ई. ई. बनाक, जहांगीरपूरी, दिल्ली—33 तथा उसके प्रबन्धकों के मन्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है;

सीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसिलये, भव, श्रीक्षोगिक विवाद भिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदर्भि की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुने हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 भिनेत, 1984 द्वारा उन्त अधिसूचना को बारा 7 के अशोन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादयस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामचा न्यायिनिर्मेष एवं पंचार तोन मात में देने हेतु निर्देश्य करने हैं जो कि उना अवश्व की तथा श्रीक है बाज या तो विवादयस्त मामचा है या विवाद से सुरंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुभाव चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है? दिनांक 28 जमवरी, 1987

स॰ घो० वि०/हिसार/1-87/4182 -- चूंकि हरिशाणा के राज्याल को राये है कि मै० नैने जिंग डायरेक्टर, दो हरिशाणा स्टेंट फीडरेंगन आफ कन्तूनर को रेटोब होत्र मेंत स्टोर लि० (कोनफीड), एस. सी. घो. 1014-15; सैक्टर 22-बी, चण्डोगढ़, (2) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हरियाणा स्टेंट फीडरेंग्रन ग्राफ कन्जूमर कोपरेटीव (कोनफीड) डिस्ट्रीक्ट ग्रांफिसर, मालगोदाम रोड, सिरसा के श्रमिक श्री दर्शन कृमार, पुत्र श्री बेली राम गांव व डा० जांडवाला बागड़, जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई भीदोगिक विवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, प्रब, श्रीद्योगिक विवाद श्रिविनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिवित्वना सं० 9641-1 श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी प्रिवित्वना की धारा 7 के श्रशीन गठित श्रम न्यायालय, रोइतक को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत का उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हे रु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उन्त प्रबन्ध को तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है :---

क्या की दर्शन कुनार की सेवाओं का समापन न्यायोजित तथा ठोक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हरुवार है?